

विकसित भारत / 2047: सामाजिक परिवर्तन, युवा शक्ति और शिक्षा की भूमिका का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

प्राप्ति: 30.08.2026

स्वीकृत: 14.09.2026

66

डॉ० अमित राहुल

प्रभारी प्राचार्य

राजकीय डिग्री महाविद्यालय, मदनपुर, औरंगाबाद, बिहार
(मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार का एक अंगीभूत महाविद्यालय)

ईमेल: rahulsociojnu@gmail.com

सारांश

भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी, वर्ष 2047, को विकसित भारत के लक्ष्य के रूप में देखा जा रहा है। यह लक्ष्य केवल आर्थिक वृद्धि अथवा सकल घरेलू उत्पाद में विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक समावेशन, मानव विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, तकनीकी नवाचार, लैंगिक समानता, पर्यावरणीय स्थिरता, सुशासन और नागरिक सहभागिता जैसे आयामों से जुड़ा व्यापक सामाजिक परिवर्तन है। प्रस्तुत अध्ययन विकसित भारत / 2047 की संकल्पना का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करते हुए युवा शक्ति और शिक्षा की केंद्रीय भूमिका की पड़ताल करता है। अध्ययन द्वितीयक स्रोतों, नीतिगत दस्तावेजों और प्रासंगिक समाजशास्त्रीय साहित्य के विश्लेषण पर आधारित है। अध्ययन का प्रमुख निष्कर्ष है कि भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश स्वतः विकास में परिवर्तित नहीं होगा; इसके लिए शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, लैंगिक समानता और सामाजिक सुरक्षा में निरंतर निवेश आवश्यक है। शोध यह तर्क प्रस्तुत करता है कि शिक्षा संस्थानों को केवल ज्ञान एवं डिग्री प्रदान करने वाले संस्थानों के बजाय मानव पूंजी, सामाजिक पूंजी, नैतिक नागरिकता और नवाचार के केंद्रों के रूप में पुनर्परिभाषित करना होगा।

मुख्य शब्द

विकसित भारत, सामाजिक परिवर्तन, युवा शक्ति, मानव पूंजी, शिक्षा

प्रस्तावना

विकास आधुनिक समाजशास्त्रीय विमर्श की केंद्रीय अवधारणाओं में से एक है। औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिकरण, वैश्वीकरण और तकनीकी परिवर्तन ने समाज की संरचना, संस्थाओं और सामाजिक संबंधों को निरंतर परिवर्तित किया है। अतः विकास को केवल आर्थिक वृद्धि के रूप में

**This article has been peer-reviewed by the Review Committee of Shodhmanthan.*

देखना समाजशास्त्रीय दृष्टि से अपर्याप्त है। किसी समाज के विकास का वास्तविक मूल्यांकन इस आधार पर भी होना चाहिए कि आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन ने मानव जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक न्याय, अवसरों की समानता, सामाजिक एकीकरण और नागरिक क्षमताओं को किस सीमा तक बेहतर बनाया है।

इसी व्यापक संदर्भ में 'विकसित भारत/2047' की अवधारणा महत्वपूर्ण हो जाती है। वर्ष 2047 भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने का प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक अवसर है। विकसित भारत की परिकल्पना का उद्देश्य भारत को एक ऐसी विकसित अर्थव्यवस्था और समाज के रूप में स्थापित करना है जो समावेशी, आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से सक्षम, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली हो। नीति आयोग के हालिया विमर्श में विकसित भारत को केवल उत्पादन या आय वृद्धि तक सीमित नहीं रखा गया है; इसमें जीवन-स्तर, शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी, नवाचार और समावेशी विकास को भी प्रमुख स्थान दिया गया है।

प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रस्तुत विकसित भारत की दृष्टि को 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के व्यापक सामाजिक दर्शन से जोड़ा गया। वर्ष 2022 में 'अमृत काल' के लिए प्रस्तुत पंच प्राण में विकसित भारत का संकल्प, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और नागरिक कर्तव्यों के निर्वहन को प्रमुखता दी गई। इन विचारों को यदि समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो इनमें आर्थिक विकास के साथ सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक आत्मविश्वास, सामूहिक पहचान और नागरिक उत्तरदायित्व के निर्माण की आकांक्षा दिखाई देती है।

भारत के लिए इस लक्ष्य का एक विशेष महत्व उसकी जनसांख्यिकीय संरचना में निहित है। भारत के पास बड़ी युवा आबादी है, जो देश के लिए संभावित जनसांख्यिकीय लाभांश का आधार बनती है। UNFPA के अनुसार भारत की जनसांख्यिकीय स्थिति एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है, लेकिन इस अवसर को वास्तविक आर्थिक लाभ में बदलना स्वतः संभव नहीं है (UNFPA 2026)। शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, लैंगिक समानता और युवाओं के अधिकारों में निवेश इसकी आवश्यक शर्तें हैं। इसलिए मूल प्रश्न यह नहीं है कि भारत के पास कितने युवा हैं, बल्कि यह है कि भारत अपने युवाओं को कितना शिक्षित, कुशल, स्वस्थ, रोजगार योग्य और सामाजिक रूप से उत्तरदायी बना पाता है।

इसी बिंदु पर शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) ने शिक्षा को केवल रोजगार प्राप्त करने के माध्यम के रूप में नहीं, बल्कि रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन, नैतिकता, संवैधानिक मूल्यों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समग्र व्यक्तित्व विकास के साधन के रूप में प्रस्तुत किया है। अतः प्रस्तुत अध्ययन का केंद्रीय तर्क है कि विकसित भारत का निर्माण अंततः विकसित मानव के निर्माण पर निर्भर करता है और विकसित मानव के निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था शिक्षा है।

अवधारणात्मक रूपरेखा

प्रस्तुत अध्ययन में विकसित भारत को पाँच परस्पर संबद्ध समाजशास्त्रीय अवधारणाओं के माध्यम से समझा गया है:

- आर्थिक पूंजी: आय, उत्पादन, रोजगार, उद्यमिता और भौतिक अवसंरचना आर्थिक विकास की आधारशिला हैं।
- मानव पूंजी: शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, ज्ञान और उत्पादक क्षमता मानव पूंजी का निर्माण करते हैं। युवा आबादी तभी राष्ट्रीय संपत्ति बनती है जब उसमें पर्याप्त मानव पूंजी का निवेश किया जाए।
- सामाजिक पूंजी: विश्वास, सामाजिक नेटवर्क, सहयोग, सहभागिता और सामुदायिक संबंध सामाजिक पूंजी के महत्वपूर्ण घटक हैं। विकसित समाज केवल आर्थिक रूप से उत्पादक नहीं बल्कि सामाजिक रूप से सहयोगी भी होना चाहिए।
- सांस्कृतिक पूंजी: भाषा, ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत, मूल्य और सामाजिक व्यवहार व्यक्ति की सामाजिक गतिशीलता और पहचान को प्रभावित करते हैं। विकसित भारत की अवधारणा में आधुनिकता और सांस्कृतिक आत्मविश्वास का संतुलन आवश्यक है।
- नागरिक एवं नैतिक पूंजी: ईमानदारी, उत्तरदायित्व, संविधान के प्रति सम्मान, लोकतांत्रिक संवाद, सहिष्णुता और सार्वजनिक हित के प्रति प्रतिबद्धता विकसित समाज की आधारभूत विशेषताएँ हैं।

इन सभी आयामों को निम्नलिखित संबंध के रूप में समझा जा सकता है:

शिक्षा → मानव पूंजी → कौशल एवं रोजगार → सामाजिक गतिशीलता → समावेशी विकास → सामाजिक एकीकरण → विकसित भारत

अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य हैं:

- विकसित भारत/2047 की अवधारणा का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना।
- भारत की युवा आबादी और जनसांख्यिकीय लाभांश की संभावनाओं का अध्ययन करना।
- विकसित भारत के निर्माण में शिक्षा एवं उच्च शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण करना।
- आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और मानव विकास के अंतर्संबंधों को समझना।
- विकास के संभावित सामाजिक एवं पर्यावरणीय दुष्परिणामों की पहचान करना।
- युवाओं में कौशल, रोजगार, नैतिकता और नागरिक उत्तरदायित्व के विकास की आवश्यकता को रेखांकित करना।
- विकसित भारत के लिए शिक्षा संस्थानों की संभावित भूमिका के संबंध में नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

चूँकि यह अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक सामग्री पर आधारित वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन है। यह अध्ययन वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं वैचारिक (conceptual) प्रकृति का है। अध्ययन के लिए द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। इनमें भारत सरकार की नीतियाँ एवं रिपोर्टें, नीति आयोग के दस्तावेज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, UNFPA की जनसांख्यिकीय रिपोर्टें, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट तथा विकास एवं सामाजिक परिवर्तन से संबंधित समाजशास्त्रीय

साहित्य शामिल हैं। अध्ययन में विषयगत अंतर्वस्तु विश्लेषण का उपयोग करते हुए विकसित भारत के विमर्श को निम्नलिखित विषयगत क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है: मानव पूंजी; युवा एवं जनसांख्यिकीय लाभांश; शिक्षा एवं कौशल रोजगार; सामाजिक समावेशन; लैंगिक समानता; डिजिटल परिवर्तन; पर्यावरणीय स्थिरता; नागरिकता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व। यह अध्ययन प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित नहीं है; इसलिए इसके निष्कर्षों को अनुभवजन्य कारणात्मक निष्कर्ष के बजाय विश्लेषणात्मक विवेचन और नीतिगत अनुशांसाओं के रूप में समझा जाना चाहिए।

विकसित भारत के लिए प्रमुख शक्तियाँ तथा चुनौतियाँ

युवा शक्ति और जनसांख्यिकीय लाभांश: भारत की युवा आबादी विकसित भारत की सबसे महत्वपूर्ण संभावनाओं में से एक है। UNFPA के अनुसार भारत की जनसांख्यिकीय संरचना एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है, किंतु जनसांख्यिकीय लाभांश स्वतः प्राप्त नहीं होता। यदि पर्याप्त रोजगार उपलब्ध न हों तो बड़ी बेरोजगारी और सामाजिक तनाव को भी जन्म दे सकती है। 2026 में UNFPA ने भी इस बात पर बल दिया कि भारत के जनसांख्यिकीय अवसर को साकार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और लैंगिक समानता में निवेश आवश्यक है। इससे स्पष्ट है कि जनसांख्यिकीय लाभांश को केवल जनसंख्या की आयु-संरचना से नहीं, बल्कि मानव क्षमता से जोड़कर देखना चाहिए।

शिक्षा और मानव पूंजी: मानव पूंजी सिद्धांत के अनुसार शिक्षा और कौशल में निवेश उत्पादकता बढ़ाता है। किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टि से शिक्षा का महत्व इससे भी व्यापक है। शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक संस्थाओं में भाग लेने, अवसरों का उपयोग करने और सामाजिक परिवर्तन को समझने की क्षमता प्रदान करती है। NEP 2020 ने इसी व्यापक दृष्टिकोण को अपनाते हुए शिक्षा में समग्र विकास, आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता, बहुविषयक अधिगम, नैतिकता तथा संवैधानिक मूल्यों को महत्वपूर्ण मानता है। अतः विकसित भारत के लिए शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करने की क्षमता नहीं बल्कि क्षमता, नागरिकता एवं चरित्र होना चाहिए।

उच्च शिक्षा की भूमिका: उच्च शिक्षा संस्थान विकसित भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। नीति आयोग के हालिया दस्तावेजों में उच्च शिक्षा को ज्ञान निर्माण, नवाचार, नेतृत्व और मानव क्षमता के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों को शोध आधारित ज्ञान उत्पन्न करना, स्थानीय समस्याओं का अध्ययन करना, नवाचार को बढ़ावा देना, रोजगारपरक कौशल विकसित करना, सामाजिक उत्तरदायित्व उत्पन्न करना एवं विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता विकसित करना चाहिए। विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित सरकारी महाविद्यालय सामाजिक परिवर्तन के स्थानीय केंद्र बन सकते हैं।

कौशल विकास और भविष्य का रोजगार: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन, डिजिटलीकरण और ग्रीन ट्रांजिशन रोजगार की प्रकृति को तेजी से बदल रहे हैं। NITI Aayog की अगस्त 2026 की रीडमैजनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत/2047 रिपोर्ट ने स्किलिंग को एक क्षेत्रीय कार्यक्रम के बजाय राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में प्रस्तुत किया है और भविष्य की अर्थव्यवस्था में ऑटोमेशन तथा ग्रीन ट्रांजिशन के कारण बदलती कौशल आवश्यकताएँ को रेखांकित किया है। इसका अर्थ है कि

शिक्षा व्यवस्था को स्थिर कौशल की बजाय आजीवन अधिगम और अनुकूलनशीलता पर जोर देना होगा। भविष्य का सफल विद्यार्थी वह नहीं होगा जिसने केवल एक कौशल सीख लिया हो, बल्कि वह होगा जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार लगातार नए कौशल सीख सके।

सामाजिक समावेशन: भारत की सामाजिक विविधता उसकी शक्ति भी है और विकास—नीति के लिए चुनौती भी। जाति, वर्ग, धर्म, लिंग और क्षेत्रीय असमानताओं के कारण शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुँच समान नहीं है। यदि विकास के लाभों का वितरण असमान रहा तो आर्थिक वृद्धि सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने के बजाय सामाजिक दूरी भी बढ़ा सकती है। इसलिए विकसित भारत का समावेशी विकास का मॉडल अपनाना होगा जिसमें कमजोर वर्गों, महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित हो।

लैंगिक लाभांश: महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक भागीदारी विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। जनसांख्यिकीय लाभांश के साथ लैंगिक लाभांश को जोड़ना आवश्यक है। NITI Aayog की हालिया रिपोर्टों में भी महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं, युवा महिलाओं और महिला उद्यमियों के लिए भविष्य—उन्मुख कौशल और गरिमापूर्ण कार्य के महत्व को रेखांकित किया गया है। इसलिए महिला शिक्षा को केवल सामाजिक कल्याण के मुद्दे के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय उत्पादकता और आर्थिक परिवर्तन की रणनीति के रूप में देखना चाहिए।

डिजिटल परिवर्तन: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारत की सामाजिक—आर्थिक संरचना को तेजी से बदल रहे हैं। डिजिटल तकनीक शिक्षा और रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकती है। लेकिन यदि डिजिटल पहुँच में सामाजिक और क्षेत्रीय असमानता बनी रहती है तो तकनीकी परिवर्तन असमानता को बढ़ा सकता है। अतः डिजिटल इंडिया को डिजिटल समावेशन में परिवर्तित करना विकसित भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता होगी।

पर्यावरण और सतत विकास: विकसित भारत का मॉडल ऐसा नहीं हो सकता जिसमें आर्थिक वृद्धि पर्यावरणीय संकट को बढ़ाए। जलवायु परिवर्तन, जल संकट, प्रदूषण, जैव—विविधता का क्षरण और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव विकास के लिए गंभीर चुनौती हैं। NITI Aayog के हालिया विकसित भारत विमर्श में आर्थिक विकास के साथ संधारणीय विकास के मार्ग, शुद्ध—शून्य उत्सर्जन और हरित परिवर्तन को जोड़ा गया है। इसलिए 2047 की विकास—यात्रा में हरित कौशल, नवीकरणीय ऊर्जा, संधारणीय कृषि, चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा जलवायु—अनुकूल एवं लचीला बुनियादी ढाँचा को महत्व देना आवश्यक होगा।

अध्ययन के विश्लेषण से पाँच प्रमुख निष्कर्ष सामने आते हैं।

1. विकसित भारत मूलतः मानव—केंद्रित परियोजना है: विकसित राष्ट्र की पहचान केवल उसकी GDP से नहीं होती। UNDP के मानव विकास दृष्टिकोण में स्वास्थ्य, शिक्षा और आय को मानव विकास के महत्वपूर्ण आयामों के रूप में देखा जाता है। भारत के HDI में भी हाल के वर्षों में सुधार हुआ है, किंतु मानव विकास की गुणवत्ता और समानता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता बनी हुई है। इसलिए विकसित भारत की सफलता का अंतिम पैमाना सामान्य नागरिक के जीवन में होने वाला सकारात्मक सुधार होना चाहिए।

2. जनसांख्यिकीय लाभांश को शैक्षिक लाभांश में बदलना: भारत की युवा आबादी अवसर है, लेकिन यह तभी लाभांश बनेगी जब युवा: शिक्षित→कुशल→स्वस्थ→रोजगारयुक्त→उत्पादक→सामाजिक रूप से उत्तरदायी बनेंगे। यदि इन चरणों में कोई महत्वपूर्ण कड़ी कमजोर रहती है, तो जनसांख्यिकीय अवसर अपेक्षित परिणाम नहीं देगा।
3. शिक्षा में चरित्र और दक्षता का समन्वय: आज के 'रोजगार बाजार' में केवल शैक्षणिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थियों में संवाद कौशल, सहयोग, रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन, डिजिटल साक्षरता और समस्या-समाधान कौशल के साथ नैतिक दक्षता भी आवश्यक है। NEP 2020 का समग्र शिक्षा मॉडल इस दिशा में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। इसमें सहानुभूति, सम्मान, लोकतांत्रिक भावना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समानता, न्याय और उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों को शिक्षा से जोड़ा गया है। अतः विकसित भारत की शिक्षा का मॉडल होना चाहिए: ज्ञान + कौशल + मूल्यबोध + नागरिक चेतना + नवाचार
4. महाविद्यालयों को स्थानीय विकास की प्रयोगशाला बनाना: विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के सरकारी महाविद्यालय स्थानीय विकास की प्रयोगशालाओं की भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए समाजशास्त्र विभाग स्थानीय स्तर पर: बेरोजगारी, प्रवासन, महिला सशक्तीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, डिजिटल विभाजन, ग्रामीण विकास पर अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार उच्च शिक्षा स्थानीय शासन और समुदाय के बीच ज्ञान सेतु का कार्य कर सकती है।
5. नागरिकता विकसित भारत की अनिवार्य शर्त है: यदि नागरिक सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा नहीं करते, कानूनों का सम्मान नहीं करते, भ्रष्टाचार को स्वीकार करते हैं और सामाजिक पूर्वाग्रहों को बनाए रखते हैं, तो केवल सरकारी निवेश विकसित भारत का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए नागरिक कर्तव्य, संवैधानिक मूल्यों और सार्वजनिक नैतिकता को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा।

समाजशास्त्रीय व्याख्या

विकसित भारत को दुर्खीम की सामाजिक एकजुटता, मैक्स वेबर का युक्तिकरण, कार्ल मार्क्स का असमानता के बारे में नजरिया और बोर्दियो का पूँजी संबंधी सैद्धांतिक ढाँचा से समझा जा सकता है। दुर्खीम के दृष्टिकोण से सामाजिक एकीकरण आवश्यक है क्योंकि अत्यधिक सामाजिक विखंडन सामाजिक अस्थिरता को जन्म दे सकता है। वेबर के संदर्भ में आधुनिक राज्य को तर्कसंगत एवं विधि-आधारित संस्थागत व्यवस्थाएँ, प्रभावी एवं उत्तरदायी नौकरशाही की आवश्यकता होगी। मार्क्सवादी दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि आर्थिक विकास के लाभों का वितरण यदि असमान रहा तो वर्गीय विषमता बनी रह सकती है। बोर्दियो के पूँजी संबंधी सैद्धांतिक ढाँचा के माध्यम से शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता को समझा जा सकता है। शिक्षा केवल आर्थिक पूँजी तक पहुँच का माध्यम नहीं बल्कि सांस्कृतिक एवं सामाजिक पूँजी के निर्माण का भी साधन है। इस प्रकार विकसित भारत का समाजशास्त्रीय मॉडल आर्थिक आधुनिकीकरण, सामाजिक समावेशन, मानव विकास, सांस्कृतिक आत्मविश्वास और लोकतांत्रिक नागरिकता का संयोजन होना चाहिए।

प्रमुख सामाजिक चुनौतियाँ

विकसित भारत की यात्रा में निम्नलिखित प्रमुख सामाजिक चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं:

- बेरोजगारी और अल्परोजगार— बड़ी युवा आबादी के लिए पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण रोजगार का निर्माण आवश्यक होगा।
- शिक्षा की गुणवत्ता— केवल नामांकन बढ़ाना पर्याप्त नहीं; अधिगम परिणाम और रोजगारपरकता भी महत्वपूर्ण हैं।
- क्षेत्रीय असमानता— राज्यों और जिलों के बीच विकास का अंतर कम करना होगा।
- ग्रामीण—नगरीय असंतुलन— अवसरों के असमान वितरण से अनियोजित प्रवासन बढ़ सकता है।
- लैंगिक असमानता— महिलाओं की शिक्षा और रोजगार भागीदारी को अधिक मजबूत करना आवश्यक है।
- डिजिटल विभाजन— तकनीकी विकास का लाभ सभी वर्गों तक पहुँचना चाहिए।
- पर्यावरणीय संकट— आर्थिक विकास को पारिस्थितिकीय स्थिरता के साथ संतुलित करना होगा।
- सामाजिक विभाजन— जाति, धर्म और अन्य पहचान—आधारित तनाव सामाजिक एकीकरण को कमजोर कर सकते हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव

महात्मा गांधी की दृष्टि में शिक्षा व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास से संबंधित थी। आज इस दृष्टि को आधुनिक संदर्भ में पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। तकनीकी दक्षता और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन ही भविष्य की शिक्षा का आधार होना चाहिए। विकसित भारत/2047 भारत की आर्थिक आकांक्षा से कहीं अधिक व्यापक सामाजिक परियोजना है। यह भारत को केवल समृद्ध नहीं बल्कि न्यायपूर्ण, समावेशी, ज्ञान—आधारित, आत्मविश्वासी, तकनीकी रूप से सक्षम और मानवीय समाज बनाने की आकांक्षा है। इस अध्ययन का केंद्रीय निष्कर्ष है कि भारत के पास एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय अवसर है, लेकिन जनसांख्यिकीय लाभांश स्वतः प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और लैंगिक समानता में निरंतर निवेश आवश्यक है।

UNFPA भी इस अवसर को नीतिगत हस्तक्षेपों से जोड़ता है। दूसरी ओर, शिक्षा को केवल रोजगारोन्मुख बनाना भी पर्याप्त नहीं होगा। विकसित भारत को ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जिनमें दक्षता के साथ चरित्र, ज्ञान के साथ प्रज्ञा तथा अधिकारों के साथ उत्तरदायित्व हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा, जो नैतिक तथा संवैधानिक मूल्यों पर आधारित हो पर जोर दिया गया है। इसलिए 2047 की तैयारी वास्तव में आज के विद्यालय और महाविद्यालय से शुरू होती है। आज का विद्यार्थी ही 2047 का शिक्षक, वैज्ञानिक, डॉक्टर, प्रशासक, उद्यमी, किसान, सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि होगा। इस दृष्टि से शिक्षा संस्थानों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल “रोजगार योग्य युवा” तैयार करना नहीं, बल्कि “राष्ट्र निर्माण योग्य नागरिक” तैयार करना है।

अंततः— विकसित भारत का निर्माण विकसित अवसंरचना से होगा, लेकिन विकसित राष्ट्र का निर्माण विकसित मनुष्य से होगा। और विकसित मनुष्य के निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। इसलिए विकसित भारत/2047 की वास्तविक यात्रा मानव पूंजी से सामाजिक पूंजी, सामाजिक पूंजी से नागरिक चेतना और नागरिक चेतना से राष्ट्र—निर्माण की यात्रा है।

संदर्भ

1. बोर्दियो, पी. (1986)। पूंजी के रूप (The Forms of Capital)। जे. जी. रिचर्डसन (सं.), शिक्षा के समाजशास्त्र के लिए सिद्धांत एवं अनुसंधान की पुस्तिका (पृ0सं0—241—258)। ग्रीनवुड।
2. दुर्खीम, ई. (1893/1984)। श्रम—विभाजन (The Division of Labour in Society)। डब्ल्यू. डी. हॉल्स (अनुवादक)। मैकमिलन।
3. गांधी, एम. के. (1953)। नई शिक्षा की ओर (Towards New Education)। नवजीवन प्रकाशन गृह।
4. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। (2020)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy 2020)। भारत सरकार।
5. नीति आयोग। (2025)। भारत दृष्टि एवं सतत विकास के मार्ग: विकसित भारत और शुद्ध—शून्य की दिशा में परिदृश्य (Bharat Vision & Sustainable Pathways: Scenarios towards Viksit Bharat and Net Zero)। भारत सरकार।
6. नीति आयोग। (2026)। विकसित भारत/2047 के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: समावेशी सामाजिक—आर्थिक विकास हेतु रणनीतिक रूपरेखा (DPI@2047 for Viksit Bharat: A Strategic Roadmap to Enable Non-linear Inclusive Socio-economic Growth)। भारत सरकार।
7. नीति आयोग। (2026ख)। विकसित भारत/2047 के लिए कौशल विकास की पुनर्कल्पना (Reimagining Skilling for Viksit Bharat/2047)। भारत सरकार।
8. नीति आयोग। (2026ग)। विकसित भारत/2047 के लक्ष्य की प्राप्ति रु उच्च शिक्षा की भूमिका (Achieving the Vision of Viksit Bharat@2047: Role of Higher Education)। भारत सरकार।
9. नीति आयोग। (2026घ)। विकसित भारत/2047 के लिए स्कूली शिक्षा (School Education for Viksit Bharat@2047)। भारत सरकार।
10. सेन, ए. (1999)। विकास एक स्वतंत्रता के रूप में (Development as Freedom)। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
11. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। (2024)। मानव विकास रिपोर्ट 2023—24: गतिरोध को तोड़ना स्वीकृत विश्व में सहयोग की पुनर्कल्पना (Human Development Report 2023—

- 24: Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World) | संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, भारत।
12. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। (2018)। भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग: नीतिगत संक्षेप (Harnessing India*s Demographic Dividend: Policy Brief)। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, भारत।
 13. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। (2022)। भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग (Reaping India*s Demographic Dividend)। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, भारत।
 14. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। (2026)। विश्व जनसंख्या दिवस: भारत का सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय अवसर उसके युवा हैं (World Population Day: India*s Greatest Demographic Opportunity is its Young People)। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, भारत।
 15. वेबर, एम. (1978)। अर्थव्यवस्था और समाज: व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की एक रूपरेखा (Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology)। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रेस।